योजना आयोग ने अब तक प्राप्त की गई प्रगति का मूल्यांकन करने और इस क्षेत्र में विस्तार की सीमा जानने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई मत्स्य पालन विकास संबंधी योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन शुरू किया है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपने केन्द्रीय अन्तर्देशीय ग्रहण मत्स्य पालन संस्थान के माध्यम से मछली की संख्या, संरक्षण का प्रबोधन करने और मात्स्य की सम्पदा का विवेकपूर्ण उपयोग करने की पद्धतियों का विकास करने की दृष्टि से 3 मुख्य नदी प्रणालियों अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा के ग्रहण मत्स्य संसाधनों का अन्वेषण कर रहा है। प्रत्येक 5 हैक्टेयर के आकार के 4 मलजल पोषण मछली फार्मों को स्थापित करने की परिकल्पना में जलकृषि के लिए जैव अवशिष्ट (मलजल) का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए 128 लाख रुपए की कुल लागत पर मंजूर की गई है। वह परियोजना गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने में सहायक होंगी।

(ग) जलाशयों में मछली पालन विकास की परियोजनाएं शुरू करने की मुख्य अड़चने पर्याप्त मात्रा में डिम्भोत्पन्न का न मिलना, जलाशय के मात्स्य की के बेहतर प्रबंध तथा उपयोग के लिए अवस्थापन त्मक सुविधाओं का न मिलना विवेकपूर्ण भंडारण, प्रबंध, संचयन तथा संचयन के बाद की प्रक्रियाओं के अभाव है। तथापि, सी० आई० सी० एफ० आर० आई० के सरोवरी मात्स्यकी प्रभाग ने देश में जलाशय मत्स्यकी तथा विकास संबंधी समस्याओं पर कार्य करना शुरु किया है। भारत सरकार के पास सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13 करोड़ रुपए की कुल लागत पर गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के राज्यों में जलाशय मात्स्यकी विकास परियोजना शुरू करने का एक प्रस्ताव भी है।

3756.[Transferred to the 9th December, 1987].

**Setting up of sugar factories in Karnataka**

3757. SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the target fixed in the Seventh Five Year Plan period for sugar production in the country, how many licences have been issued for expansion and seting up of new industries in the country upto the end of October, 1987 and to what capacity; and

(b) how many applications have been received from Karnataka for expansion and setting up of new sugar industries how many of them are pending for issue of licences till the end of October, 1987?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H K L. BHAGAT): (a) In the Seventh Plan document a production target of 102 lakh tonnes of sugar for 1989-90 is envisaged. After the announcement of new guidelines for licensing in the Sugar Industry during the Seventh Five Year Plan, 11 Letters of Intent for establishment of new 2500 TCD sugar plants and 39 for substantial expansion in the expasion and settig up of new sugar production capacity of 9.81 lakh tonnes have been issued upto 31st October, 1987.

(b) (i) Applications received for setting up of new sugar units—Nil.

(ii) Applications received and approved for expansion in the existing units—3.

(iii) Applications pending—Nil.

**National Fertilizer unit at Vijaypur in Madhya Pradesh**

3758. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the National Fertilizers Limited unit at Vijaypur in Madhya Pradesh